भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1392
रविवार, 20 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए नियत

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि

1392. श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत मध्य प्रदेश को निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में ऐसे आकांक्षी जिलों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा उक्त निधि के व्यय की निगरानी करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग): भारी उद्योग विभाग, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधि को सीधे आवंटित अथवा निगरानी नहीं करता है। यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किया जा रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), जो इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है ने मध्य प्रदेश के पाँच आकांक्षी जिलों नामतः दामोह, गुना, खण्डवा, राजगढ़ और विदिशा में वर्ष 2018-19 और 2019-20 में ₹7.36 लाख खर्च किए हैं।

*****